कश्मीर के बारे में अमरीका की राय

3903. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**

श्री राम जेठमलानी :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जुलाई, 1993 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में "कश्मीर इज डिस्प्यूटिड टेरिटरी : यू० एस० ऑफिशियल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अमरीका सरकार ने गत दो माह से कश्मीर विवाद के बारे में अपनी राय बदल ली है;

(ग) यदि नहीं, तो तथ्य क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि अमरीकी सरकार द्वारा कश्मीर पर कायम उक्त राय तथ्यों पर आधारित नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने अमरीका सरकार से अपनी राय तथ्यों के आधार पर कायम करने का आग्रह किया है; और

(च) यदि हां, तो अब अमरीका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सरकार को सूचित की गई अमरीका की स्थिति यह है कि अमरीका वास्तविक नियंत्रण रेखा के दोनों ओर कश्मीर को विवादास्पद प्रदेश मानता है । हाल ही में अमरीका ने अपनी नीति में एक यह नई बात जोड़ी है कि वह यह चाहता है कि कश्मीरी लोगों के विचारों को ध्यान में रखते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच यह समस्या शांतिपूर्ण ढंग से हल हो जानी चाहिए । यदि भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस प्रक्रिया में अमरीका की सहायता चाहते हों तो वह सहायता करने के लिए तैयार है ।

(घ) और (ङ) कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की वास्तविकताओं तथा भारत में आतंकवाद की सहायता करने तथा उसे दुष्प्रेरित करने में पाकिस्तान का हाथ होने के बारे में सरकार अमरीका की सरकार को बराबर अवगत कराती रही है। सरकार यह बात जोर देकर कहती रही है कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है ।

(च) अमरीका की सरकार ने यह कहा है कि अमरीका को यह बात तय नहीं करनी है कि कश्मीरियों के विचारों को किस प्रकार ध्यान में रखा जाना चाहिए । अमरीका की सरकार ने पाकिस्तान को यह भी कहा है कि अमरीका इस बात पर बराबर निगाह रख रहा है कि पाकिस्तान द्वारा राज्य प्रायोजित आतंकवाद को लेकर अमरीका को जो चिंता है उसे दूर करने में पाकिस्तान क्या कर रहा है । बताया जाता है अमरीका ने पाकिस्तान को यह चेतावनी दी है कि यदि उसका सकारात्मक रवैया बरकरार नहीं रहता, अथवा यदि भारत में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान की सरकारी मदद प्रत्यक्षतः अथवा गैर-सरकारी स्रोतों के जरिये किसी रूप में फिर से शुरू की जाती है तो अमरीका के विदेश मंत्री को पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजकी राज्य के रूप में सूचीबद्ध करने में कोई संकोच नहीं होगा ।

चार 'दक्षेस' देशों के साथ बातचीत

3904. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना नदियों पर पन-बिजली परियोजनाओं की स्थापना करके इस संपूर्ण क्षेत्र को विकसित करने की संभावनाओं को मूर्तरूप देने तथा सात दक्षेस देशों में से चार देशों को लाभान्वित करने की दृष्टि से बांगलादेश, भूटान, नेपाल और भारत के बीच कोई बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है तो क्या सरकार भविष्य में इस दिशा में कोई कार्यवाही करेगी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (ग) पन-बिजली परियोजनाएं लगाने के संबंध में बांगलादेश, भूटान, नेपाल और भारत के बीच कोई विचार-विमर्श तो नहीं हुआ है लेकिन सरकार ने अनेक पन-बिजली परियोजनाओं के संबंध में संबंधित देशों के साथ द्विपक्षीय विचार-विमर्श किए हैं और आपसी लाभ के लिए कुछ परियोजनाएं क्रियान्वित भी की हैं ।

सरकार आपसी लाभ की पन-बिजली परियोजनाएं संबंधित देशों के सहयोग से स्थापित करने को महत्व प्रदान करती है ।

Ex-Ambassador's Link with Dawood Ibrahim

3905. PROF. SAURIN BHATTACHARYA : Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an ex-Ambassador in U.S.A. was discredited for his links with Dawood Ibrahim and Win Chadha.

(b) whether it is a fact that normally a diplomat is not assigned to the same country twice;

(c) if so, why this ex-Ambassador with a dubious record is being sought to be reassigned to the U.A.E. and

(d) whether any step will be taken by Government to prevent such reassignment and bring to book those responsible for attempt to send him back to U.A.E. as India's Ambassador?

THE MINISTER OF STATE IN THE